संशोधित अनुमान 2010-2011

वर्ष 2010-11 के लिए व्यय के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 107827 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शायी गई है। आयोजना-भिन्न व्यय में ₹ 85895 करोड़ की वृद्धि देखी गई है, वहीं आयोजना व्यय में ₹ 21932 करोड़ की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख मदों में घट-बढ़ हुई, है उन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपए)

		बजट 2010-11	संशोधित 2010-11	घट-बढ़ बचत(-)/ आधिक्य(+)
आयोजना-भिन्न				
1.	पेट्रोलियम सब्सिडी	3108	38386	(+) 35278
2.	पेंशन	42840	53262	(+) 10422
3.	खाद्य सब्सिडी	55578	60600	(+) 5022
4.	उर्वरक सब्सिडी	49981	54976	(+) 4995
5.	अन्य सब्सिडियां	7557	10191	(+) 2634
6.	पुलिस	22154	27587	(+) 5433
7.	रक्षा सेवा व्यय	147344	151582	(+) 4238
8.	राज्यों को अनुदान	45119	51756	(+) 6637
9.	डाक संबंधी घाटा	3596	5854	(+) 2258
10.	अन्य आयोजना भिन्न व्यय	78665	98905	(+) 20240
11.	ब्याज संदाय और ऋण शोधन	248664	240757	(-) 7907
12.	पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	31051	27696	(-) 3355
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय		**735657**	**821552**	**(+) 85895**
आयोजना				
1	केन्द्रीय आयोजना	280600	298612	(+) 18012
2	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	92492	96412	(+) 3920
जोड़ (आयोजना) व्यय		**373092**	**395024**	**(+) 21932**
कुल व्यय (आयोजना + आयोजना-भिन्न)		**1108749**	**1216576**	**(+)107827**

आयोजना-भिन्न

1. यह वृद्धि मुख्यतया तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज़) को अधिक पेट्रोलियम सब्सिडी देने के कारण है।

2. यह वृद्धि मुख्यतया 1.1.2006 से अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों (पीबीओआर) के पेंशन में सुधार करने के संबंध में सरकार के आदेशों को लागू करने तथा रक्षा पेंशनों के अन्तर्गत महंगाई राहत की उच्चतर दरों के प्रभाव के कारण है।

3. यह वृद्धि मुख्यतया बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को भुगतान और राज्यों को अनाज के बढ़े हुए आवंटन के कारण है।

4. वृद्धि मुख्यतया स्वदेशी यूरिया और विकेन्द्रीकृत उर्वरकों की उच्चतर आर्थिक लागत के कारण है।

5. यह वृद्धि मुख्यतया नेफेड और सीसीआई को कपास की अधिप्राप्ति के लिए उच्चतर सब्सिडी, किसानों को अल्पावधिक ऋण उपलब्ध कराने, निर्यात संवर्धन के तहत बैंकों से ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने तथा खाद्य तेलों/दलहनों आदि के आयात पर सब्सिडी देने के कारण है।

6. यह वृद्धि मुख्यतया आंतरिक सुरक्षा पर अतिरिक्त व्यय के कारण हुई।

7. यह वृद्धि मुख्यतः स्थापन व्यय तथा पूंजी पक्ष के ओर से अतिरिक्त केन्द्रीय व्यय के कारण है।

8. यह वृद्धि मुख्यतः जम्मू तथा कश्मीर को विशेष योजना सहायता, विशेष श्रेणी के राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के उच्चतर प्रावधानों के कारण है।

9. यह वृद्दि मुख्यतः डाक विभाग की वेतन तथा पेंशन के लिए बढ़ी हुई जरूरतों के कारण हुई है।

10. समग्र तौर पर यह कमी कार्यनिष्पादन के आधार पर और सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण राजस्व हानियों हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों हेतु कम प्रावधान के निवल प्रभाव के कारण है।

11. ब्याज भुगतान में बचतों के कारण।

12. मुख्यतः अनुसंधान (पुलिस) पर पूंजी परिव्यय हेतु भत्ता अपेक्षाओं, सीमा सड़क के विनिर्माण कार्यों तथा विश्व बैंक ऋण के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण के कारण।

आयोजना

1. यह समग्र वृद्धि कृषि, रसायन एवं पैट्रोरसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, वन एवं पर्यावरण, वित्तीय सेवाएं, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता, श्रम एवं रोजगार, सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, शहरी विकास तथा रेल में वृद्धि के निवल प्रभाव तथा डाक, दूरसंचार, आर्थिक कार्य, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलें, योजना, विद्युत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अंतरिक्ष. सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, जलसंसाधन तथा महिला एवं बालविकास में कमी के कारण है।

2. समग्र वृद्धि विशेष आयोजना सहायता, संसद सदस्यों की स्थानीयक्षेत्र विकास स्कीम, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में वृद्धि तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन शामिल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में कमी के निवल प्रभाव के कारण है।